MSNTARGET.COM

https://msntarget.com

सोनम वांगचुक अस्पताल में, भड़के खरगे- सरकार ने किसी को नहीं बख्शा

विषय सूची (Table of Contents):

>> सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, 21वें दिन जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट...

>> सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती...

>> समर्थकों में भारी आक्रोश...

>> इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा , मल्लिकार्जुन खरगे का केंद्र पर तीखा हम...

>> मल्लिकार्जुन खरगे का आधिकारिक बयान...

>> किसान, पहलवान और छात्र खरगे ने गिनाईं सरकार की ज्यादतियां...

>> प्रमुख आंदोलनों का किया जिक्र...

>> आवाज उठाने वालों को बताया जाता है एंटी-नेशनल , कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप...

>> परजीवी और एंटी-नेशनल का टैग...

>> युवाओं और छात्रों का बढ़ता आंदोलन...

>> लोकतंत्र और संविधान पर एक और काला धब्बा जंतर-मंतर की घटना पर भड़की कांग्रेस...

>> संवैधानिक मर्यादाओं के हनन का आरोप...

>> डॉक्टरों की सलाह और हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस का एक्शन...

>> हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला...

>> वांगचुक के समर्थकों की अपील सरकार फौरन शुरू करे बातचीत और सुने मांगें...

>> समर्थकों की प्रमुख मांगें...

>> निष्कर्ष (Conclusion)...

>> आपके सवाल, हमारे जवाब...

देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर सामने आ रही है. जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा धरना स्थल से हटा दिया गया है. इस घटनाक्रम के बाद देश का सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

एक तरफ जहां प्रशासन इसे स्वास्थ्य और कानूनी सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे तानाशाही की पराकाष्ठा करार दिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है और इसे लोकतंत्र पर एक और बड़ा आघात बताया है. आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम काlatest updateऔर इस पर हो रही सियासत की पूरी इनसाइड स्टोरी.

सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, 21वें दिन जंतर-मंतर से सफदरजंग

लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और पर्यावरण संरक्षण जैसी विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. शनिवार, 18 जुलाई 2026 को उनके इस आमरण अनशन का 21वां दिन था. लंबे समय से अन्न का त्याग करने के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था.

सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती

शनिवार को अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई. इसके तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और सुरक्षाबलों की मौजूदगी में सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम की देखरेख में उनका इलाज और मेडिकलstatus checkजारी है.

समर्थकों में भारी आक्रोश

जैसे ही सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की खबर फैली, जंतर-मंतर पर मौजूद उनके समर्थकों और लद्दाख से आए लोगों में भारी असंतोष देखने को मिला. समर्थकों का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांगों को सुनने के बजाय उनके आंदोलन को जबरन कुचलने का प्रयास कर रही है. हालांकि, पुलिस का दावा है कि यह कदम पूरी तरह से उनके जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है.

इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा , मल्लिकार्जुन खरगे क

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने की घटना के तुरंत बाद राजनीति के गलियारों में भूचाल आ गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक लंबा पोस्ट साझा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. खरगे ने सरकार की कार्यप्रणाली को तानाशाही करार दिया है.

मल्लिकार्जुन खरगे का आधिकारिक बयान

कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा, 111 दिन तक माँ गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रो॰ जी डी अग्रवाल हों या हरियाणा की ओलंपिक रेसलर हों, हमारे 750 अन्नदाता किसान हों, दलित-आदिवासी हों, या फिर पेपर लीक की बलि चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन... इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा. इनकी नज़र में कोई भी देशवासी सुरक्षित नहीं है.

किसान, पहलवान और छात्र: खरगे ने गिनाईं सरकार की ज्यादतियां

मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयान में केवल सोनम वांगचुक के मुद्दे तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हुए देश के बड़े आंदोलनों का जिक्र करते हुए सरकार के इतिहास पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार हर उस वर्ग को प्रताड़ित करती है जो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है.

प्रमुख आंदोलनों का किया जिक्र

>> प्रोफेसर जी. डी. अग्रवाल:गंगा नदी के संरक्षण के लिए 111 दिनों तक आमरण अनशन करने वाले पर्यावरणविद् प्रो. अग्रवाल का उदाहरण देते हुए सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए.

>> हरियाणा के ओलंपिक पहलवान:जंतर-मंतर पर न्याय के लिए महीनों प्रदर्शन करने वाली महिला रेसलर्स के साथ हुए व्यवहार को याद दिलाया.

>> 750 अन्नदाता किसान:तीन कृषि कानूनों के विरोध में चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 750 से अधिक किसानों की शहादत का जिक्र किया.

>> पेपर लीक से प्रभावित छात्र:हाल के दिनों में हुए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और भ्रष्टाचार से पीड़ित 25 युवाओं और उनके परिवारों के दर्द को साझा किया.

विभिन्न सरकारी योजनाओं और नियमों की कानूनी बारीकियों को समझने के लिए आप सरकार के आधिकारिकइंडिया कोड पोर्टलपर जाकर सभी राष्ट्रीय नियमों कीPDF listदेख सकते हैं और कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

आवाज उठाने वालों को बताया जाता है एंटी-नेशनल , कांग्रेस अध्

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार की मानसिकता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान शासनकाल में असहमति की आवाज को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह सरकार इस अधिकार को छीन रही है.

परजीवी और एंटी-नेशनल का टैग

खरगे ने अपने पोस्ट में लिखा कि सरकार की नजर में जो भी नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करता है या नीतियों की आलोचना करता है, उसे तुरंत एंटी-नेशनल (देशद्रोही) या परजीवी कह दिया जाता है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों को बदनाम करना इस सरकार की रणनीति बन चुकी है.

युवाओं और छात्रों का बढ़ता आंदोलन

इसके साथ ही उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे छात्र आंदोलनों का भी समर्थन किया. खरगे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कोटा और देहरादून जैसे शिक्षा केंद्रों से शुरू हुई छात्रों की गूंज की आवाज अब बहुत जल्द दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचेगी और सरकार को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जवाब देना होगा. खेल जगत की अन्य खबरों और दिल्ली से जुड़े घटनाक्रमों के लिए आपकूपर कोनोली और दिल्ली मैच अपडेटकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं.

लोकतंत्र और संविधान पर एक और काला धब्बा: जंतर-मंतर की घटना प

जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने की इस कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी ने देश के लोकतंत्र के लिए एक बेहद दुखद और शर्मनाक दिन बताया है. विपक्षी नेताओं का मानना है कि जंतर-मंतर को हमेशा से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का प्रतीक माना गया है, लेकिन वहां से एक गांधीवादी आंदोलनकारी को हटाना तानाशाही का प्रमाण है.

संवैधानिक मर्यादाओं के हनन का आरोप

विपक्ष ने कहा कि यह घटना भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक और गहरा काला धब्बा है. सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं और पुलिस बल का दुरुपयोग कर रही है. कांग्रेस के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार कर ली है.

डॉक्टरों की सलाह और हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस का ए

विपक्ष के इन तमाम गंभीर आरोपों और चौतरफा हमलों के बीच दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने भी इस मामले पर अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखा है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से मानवीय और कानूनी आधार पर की गई है.

हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला

दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सोनम वांगचुक का अनशन 21वें दिन में प्रवेश कर चुका था और उनकी शारीरिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी थी. डॉक्टरों की टीम ने तुरंत मेडिकल हस्तक्षेप की सलाह दी थी. इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही उन्हें सुरक्षित तरीके से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई गंभीर नुकसान न पहुंचे.

वांगचुक के समर्थकों की अपील: सरकार फौरन शुरू करे बातचीत और स

सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी लद्दाख से आए प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों का हौसला कमजोर नहीं हुआ है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका यह वैचारिक आंदोलन जारी रहेगा.

समर्थकों की प्रमुख मांगें

वांगचुक के समर्थकों ने मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील की है कि वह तानाशाही रवैया छोड़कर तुरंत बातचीत की प्रक्रिया शुरू करे. उनकी मुख्य मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, पर्यावरण को उद्योगपतियों के शोषण से बचाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की है. उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जो उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करे.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने के इच्छुक युवा सरकारी योजनाओं के तहत लोन के लिएapply onlineकर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आप गांव में बंपर कमाई और बिजनेस लोन की इस विस्तृत रिपोर्ट में देख सकते हैं.

निष्कर्ष (Conclusion)

सोनम वांगचुक का 21 दिनों तक चला अनशन और उसके बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ यह घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि आने वाले दिनों में लद्दाख का मुद्दा और अधिक तूल पकड़ने वाला है. जहां प्रशासन इसे स्वास्थ्य कारणों से की गई कार्रवाई बता रहा है, वहीं मल्लिकार्जुन खरगे के तीखे बयानों ने इसे सीधे तौर पर सरकार की तानाशाही और दमनकारी नीतियों से जोड़ दिया है.

लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा हथियार होता है. अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र सरकार सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों की मांगों पर विचार करने के लिए आगे आती है, या फिर यह राजनीतिक गतिरोध देश में एक और बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा. इस मामले से जुड़ी हरlatest updateके लिए हमारे साथ बने रहें.

आपके सवाल, हमारे जवाब

दिल्ली पुलिस के अनुसार, उनके अनशन के 21वें दिन उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. डॉक्टरों की मेडिकल सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है और उनका इलाज जारी है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि यह सरकार तानाशाह है और जो भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, उसे

एंटी-नेशनल या परजीवी कह दिया जाता है.

उन्होंने प्रो. जी डी अग्रवाल के गंगा संरक्षण अनशन, हरियाणा की महिला पहलवानों के प्रदर्शन, किसान आंदोलन (750 किसानों की मौत) और पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के आंदोलनों का जिक्र किया.

वह मुख्य रूप से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करने, पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख के नाजुक पर्यावरण की रक्षा करने की मांग कर रहे थे.

समर्थकों ने मांग की है कि सरकार बल प्रयोग बंद करे और लद्दाख की समस्याओं व मांगों के निवारण के लिए तुरंत उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करे.

जी हां, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसी पार्टियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताते हुए आगामी सत्रों में सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं.

नहीं, उनके समर्थकों का कहना है कि यह एक वैचारिक लड़ाई है और अस्पताल से छुट्टी मिलने या सरकार द्वारा कोई ठोस आश्वासन मिलने तक उनकी मांगें और आंदोलन जारी रहेगा.